193 सदस्य देशों को कोरोना वायरस से किस प्रकार निपटना चाहिए, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो प्रस्ताव पेश किए गए हैं। वैश्विक संस्था की इन दिनों बैठकें नहीं हो रही हैं और इसके कारण मतदान के नियमों में बदलाव किया गया है।

कोरोना पर न्यूनतम साझा राहत कार्यक्रम लाए सरकार : सोनिया

हालात पर चर्चा ▶ कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सभी वर्गों को राहत देने की उठाई मांग

लॉकडाउन का किया समर्थन, अधूरी तैयारी से पैदा हुई समस्याओं पर सरकार को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संकट और लॉकडाउन से बढ़ी दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से न्यूनतम साझा राहत कार्यक्रम तत्काल लागू करने की मांग की है। इस अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से कहा, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसलिए सरकार को न्यूनतम साझा राहत कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए। कार्यसमिति ने लॉकडाउन को जरूरी तो बताया मगर इसे आपाधापी में बिना तैयारी लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा।

सोनिया ने कहा, लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जिस तरह इसे लागू किया गया उसने लाखों प्रवासी कामगारों का रोजगार छीनकर उन्हें पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने गांवों की ओर भागने पर विवश कर दिया। केंद्र ने सीमित टेस्टिंग की नीति अपनाकर भी भारी गलती की है और लॉकडाउन का मकसद तब तक

सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यसमिति को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित किया। एएनआइ

निरर्थक है जब तक विस्तृत टेस्टिंग नहीं की जाती। डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को डब्ल्यूएचओ मानक के बचाव मास्क, बॉडीसूट व अन्य उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं कराना भी उचित नहीं है।

कार्यसमिति ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं इनमें मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने, गरीब तबकों, किसानों के साथ-साथ जिनका रोजगार छीन गया है उनके लिए रोजी-रोटी का इंतजाम, लॉकडाउन में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता व कालाबाजारी पर रोक के कदम उठाना शामिल हैं। गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने को हरसंभव समाधान निकालने, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए मदद मुहैया कराने को भी पार्टी ने अपरिहार्य बताया है। सोनिया ने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की।

राहुल बोले, बचाव के लिए चाहिए विशिष्ट रणनीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मनमोहन और प्रियंका ने भी कार्यसमिति में कोरोना संकट पर रखी अपनी बात
- पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमें निभानी होगी वॉचडॉग की भूमिका

कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यसमिति की बैठक में भारत के लिए तुरंत विशिष्ट रणनीति बनाए जाने की जरूरत बताई है। साथ ही कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली सबसे ज्यादा मुश्किलों को देखते हुए कांग्रेसजनों से बुर्जुगों को खास मदद देने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ाई की चुनौती में कांग्रेस देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए भारत की जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट रणनीति बनाने की बात उठाने की जानकारी खुद ही ट्वीट के जरिये दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस रणनीति की हमें आपात जरूरत है। लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के खाने-पीने और रहने का प्रबंध किए बिना ऐसी बंदी कभी नहीं की। मौजूदा हालात में भारत को आर्थिक तबाही के लिए भी तैयार रहना होगा। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में पूरा साथ देते हुए भी कांग्रेस को एक वॉचडॉग की भूमिका निभानी होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों को सबसे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है और ऐसे कई हृदयविदारक दृश्य दिखे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया।

प्रियंका ने लॉकडाउन से बढ़ी आर्थिक मुसीबत में बच्चों की स्कूल फीस को बड़ी चुनौती बताते हुए अभिभावकों को इससे राहत देने की जरूरत बताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा मजदूरों समेत सोनिया गांधी के दिए सुझावों के मामले को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उठाने की बात कही। पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार संकट की गहराई को नहीं समझ पाई है इसीलिए जरूरी है कि कांग्रेस कोरोना की लड़ाई में सरकार का समर्थन करते हुए भी लगातार उसकी कमियों को बताती रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य की कई मदों में लंबित हजारों करोड़ की राशि नहीं मिलने की बात उठाई। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, यह हकीकत है कि मीडिया हमारे सुझावों को दिखाने से इन्कार कर रहा है मगर इसके बावजूद कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती।

गरीबों की मदद के लिए आगे आएं धार्मिक संस्थाएं : प्रियंका

लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और मजदूर वर्ग की रोजी-रोटी पर आए संकट को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी धार्मिक संस्थाओं को पत्र लिखकर इनकी मदद की अपील की है। मठों-मंदिरों, डेरों, इदारों, गुरुद्वारों और चर्चों से जुड़े धार्मिक संगठनों के प्रमुखों से की गई इस अपील में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से गरीबों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। मजदूरों के काम बंद हो गए हैं और रेहड़ी-पटरी वालों का रोजगार ठप हो गया है जिसके चलते रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित लोगों की भूख से व्याकुलता की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में इंसानियत की सेवा कर रहीं सभी धर्मों की संस्थाओं से अपील है कि ऐसे लोगों को खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस काम में मदद को कहा है।

राष्ट्रहित से ऊपर राजनीति कांग्रेस की पुरानी सोच : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इसी नीति के कारण कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया था
- जान बचाने को लोगों ने लॉकडाउन को अपनाया, पर कांग्रेस को आपत्ति

कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया ने खुद कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरीखे नेताओं ने जहां सरकार और देश के साथ खड़े होने की बात की है। वहीं सोनिया गांधी व राहुल गांधी समेत कुछ नेता नुक्ताचीनी में जुटे दिखे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर समेत कइयों ने कांग्रेस को नसीहत दी कि ऐसी आपदा के समय में राजनीति छोड़कर केवल राष्ट्रहित की बात सोचें और लोगों को भ्रमित करना छोड़ें।

शाह ने ट्वीट के जरिए कहा, 'पूरा देश कोरोना को हराने में एकजुट है। विश्व इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों की प्रशंसा कर रहा है तो कांग्रेस राष्ट्रहित को भूलकर राजनीति कर रही है।' कांग्रेस की पुरानी आदत है कि राष्ट्रीय हित के मामले में वह अलग राह चलती है। इसी नीति के कारण देश का बंटवारा भी हुआ। नड्डा और जावडेकर ने याद दिलाया कि लॉकडाउन वक्त की जरूरत है। आज जबकि पश्चिम के कई देशों में स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है तो भारत इसकी गति को थामने में अब तक कामयाब रहा है। डब्ल्यूएचओ भी इसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन जमीन खो चुके कांग्रेस नेताओं के लिए यह भी राजनीति का अवसर है। दोनों नेताओं ने कहा, अभी लोगों को जागरूक कर उन्हें, उनके परिवारों को बचाने का वक्त है तो सोनिया और राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। गरीब, मध्यमवर्ग, उद्योग को इस नाजुक दौर में मदद करने के लिए पैकेज का भी इंतजाम किया गया है। 1.70 लाख करोड़ के पैकेज से गरीबों को राहत दी गई है। नड्डा ने याद दिलाया कि 21 दिन का लॉकडाउन घोषित होने से पहले ही कई राज्यों में और देश के 70 फीसद हिस्से में लॉकडाउन हो चुका था या फिर ऐसी स्थिति बन गई थी। इसमें पंजाब और राजस्थान भी शामिल था। तो क्या सोनिया गांधी कहेंगी उनके मुख्यमंत्रियों ने भी बिना तैयारी के लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। प्रधानमंत्री खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर कोरोना को हराने की कोशिश मे जुटे हैं।

न्यूज गैलरी

बाल सुधार गृहों पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देशभर में स्थित बाल सुधार गृहों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 16 मार्च को देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने के मामले का संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 मार्च को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समिति गठित कर ऐसे दोषियों और विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने को कहा था, जिनके अपराधों की अधिकतम सजा सात साल है। उसने बाल सुधार गृहों व बाल संरक्षण गृहों में कोरोना वायरस की रोकथाम पर भी विचार किया था। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा था कि स्कूली बच्चों को किस तरह से मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। (प्रेट्र)

कोरोना से लड़ाई में भूतपूर्व सैनिक भी जुटेंगे : रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह अपने रिटायर जवानों को एकजुट कर रहे हैं ताकि राज्य और जिला स्तर या जहां कहीं भी जरूरत हो सहायता पहुंचाई जाए। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में रिटायर सैनिकों को जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ताकि ये राज्य और जिला प्रशासन को लोगों तक पहुंचने में सहायता कर सकें। इसमें संपर्क का पता लगाना, सामुदायिक निगरानी, पृथक केंद्र का प्रबंधन और उनको दिया जाने वाला कार्य शामिल है।' रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में पूर्व सैनिकों के एक संगठन में 4,200 रिटायर सैनिक हैं और वे सभी गांवों से आंकड़े जुटाने में मदद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ईएसएम को पुलिस की सहायता के कार्य में लगाया है और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी जिला कलेक्टरों ने ईएसएम स्वयंसेवियों से सहायता मांगी है। उत्तर प्रदेश में सभी 'जिला सैनिक कल्याण अधिकारी' जिला नियंत्रण कक्ष के संपर्क में हैं। रिटायर आर्मी मेडिकल कोर के कर्मियों की भी पहचान की गई है और उन्हें तैयार रखा गया है। (प्रेट्र)

दवाओं की कमी पर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने की बात

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य उपकरणों और दवाओं की कमी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जर्मनी की चांसलर एंजिला मार्केल के साथ विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने इस संकट में आपसी सहयोग को लेकर भी प्रतिबद्धता जाहिर की। साथ ही पीएम मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुर्वेद के फायदों पर भी चर्चा की।

पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी और मार्केल के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अपने-अपने देश में इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार उन्होंने दवाओं और मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की। साथ ही दोनों नेता आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने पर सहमत हुए।

जर्मनी की चांसलर इस बात पर पीएम मोदी के साथ सहमत दिखीं कि आधुनिक

- प्रधानमंत्री ने कहा-योग और आयुर्वेद से बढ़ा सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता

नरेंद्र मोदी। फाइल

इतिहास में कोविड-19 एक बेहद ही अहम मोड़ साबित हुआ है। इससे हमें आपसी भाईचारे और वैश्वीकरण के नए आयाम तलाशने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने एंजिला मार्केल को योगासन और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आसान तरीकों को लेकर भारत की पहल के बारे में बताया। वह भी इस बात से सहमत दिखीं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना काफी फायदेमंद हो सकता है।

देश के संविधान की शपथ लेने वाले पहले जस्टिस बने रजनीश

जेएनएन, जम्मू : जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जस्टिस ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपना पदभार संभाला है। जस्टिस रजनीश ओसवाल को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गुरुवार को शपथ दिलवाई। इसके साथ जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जजों की संख्या नौ हो गई है। अब तक जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जजों को जम्मू कश्मीर संविधान की शपथ दिलवाई जाती थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जजों को यहां पर भारत के संविधान की शपथ दिलवाई जाएगी।

जस्टिस रजनीश की नियुक्ति की अधिसूचना 20 जनवरी 2020 को जारी हुई थी। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद रजनीश पहले ऐसे वकील हैं जिन्हें जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई। जम्मू में 17 जून 1973 को जन्में एडवोकेट रजनीश ने डीबीएन स्कूल मुबारक मंडी से प्राथमिक शिक्षा हासिल की।

राज्यसभा के नए सांसदों की अभी नहीं होगी शपथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लॉकडाउन के चलते 37 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टाला

लॉकडाउन की वजह से राज्यसभा के नवनिर्वाचित 37 सदस्यों को अभी शपथ नहीं दिलाई जा सकेगी। हालांकि, संसद में वोटिंग के अधिकार के अलावा इन सदस्यों को वेतन और भत्ते समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा है कि मौजूदा हालात में नए सदस्यों का शपथ जरूरी नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही इस संवैधानिक अनिवार्यता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से सभी नए सदस्यों को तत्काल शपथ की जरूरत नहीं होने की सूचना भेज दी गई है। विधायी हिसाब से संसद सदस्य चुने जाने के बाद शपथ लेने के बाद ही वह सदन की कार्यवाही या स्थाई समितियों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। शपथ लिए बिना वे सदन में किसी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। राज्यसभा की नियमावली में नए सदस्य के शपथ लेने की ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। नायडू की ओर से नए सदस्यों को संदेश भेजा गया है कि तत्काल शपथ नहीं लेने से सांसद के तौर पर उनके अधिकार और सुविधाओं पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन में सदन या समिति की कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। शपथ नहीं लेने के बावजूद सांसदों को वेतन-भत्ते और सभी विशेषाधिकार व सुविधाएं तत्काल प्रभाव से ही मिलेंगी।

गौरतलब है कि राज्यसभा के 55 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में 37 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। दो अप्रैल से इनकी सदस्यता का कार्यकाल शुरू हो गया है जबकि 18 सीटों पर चुनाव बीते 26 मार्च को होने थे। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने इन 18 सीटों का चुनाव स्थगित कर दिया है।

अब तक की रणनीति सफल

प्रथम पृष्ठ से आगे

कोरोना फैलने से रोकने में अब तक की रणनीति को सफल बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद देश के कुछ इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए हैं। इनमें मुंबई और दिल्ली के कुछ इलाकों जैसे देश के कई स्थानों पर एक जगह से बड़ी संख्या में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और वहां सैकड़ों लोग आइसोलेशन में रखे गए हैं। चूंकि कोरोना से ग्रसित ये लोग लंबे समय से इन इलाकों में खुलेआम घूम रहे थे इसीलिए यहां कोरोना के एक बड़ी जनसंख्या में फैले होने की आशंका बढ़ गई है। समस्या यह है कि ऐसे इलाकों में कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद लोगों में बीमारी के लक्षण आने में कई दिन लग सकते हैं, तब तक वायरस के कई अन्य लोगों में फैलने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। वैसे लॉकडाउन की वजह से इस वायरस के उक्त इलाके से बाहर जाने की आशंका कम है, लेकिनजरूरी चीजें लाने ले जाने के दौरान संक्रमण फैल सकता है।

कुछ विदेशी नागरिकों को एयर इंडिया की चार्टर्ड उड़ानों से स्वदेश भेजेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड और जर्मनी के साथ विशेष समझौते किए
- विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड उड़ानों से स्वदेश लाने पर अभी निर्णय नहीं

भारत में फंसे विदेशियों को निकालने तथा उनके संबंधित देशों तक पहुंचाने के लिए एयर इंडिया विशेष चार्टर्ड उड़ानें शुरू करेगी। इसकी शुरुआत जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और कनाडा के नागरिकों को भेजे जाने से होगी। परंतु विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चार्टर्ड उड़ानों को अनुमति अभी नहीं दी गई है। ध्यान रहे कि 14 अप्रैल तक हर अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर पाबंदी है।

नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को पहुंचाने के लिए भारत संबंधित देशों के अनुरोध पर विचार करते हुए उन देशों के लिए चार्टर्ड उड़ानों की अनुमति देगा। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को अप्रत्याशित बताते हुए पुरी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट नए तरीके अपना रहे हैं। एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने बताया कि एयर इंडिया ने चार देशों- जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड के साथ अनुबंध किए हैं। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक, ये उड़ानें एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों के माध्यम से होंगी। और इनके लिए पूरे विमान का नियमित किराया लिया जाएगा।

15 अप्रैल तथा उसके बाद की तारीखों के लिए एयरलाइंस द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने के सवाल पर नागर विमानन मंत्री ने कहा कि ये एयरलाइंस पर है कि वह क्या करती हैं। हमने इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है। यदि उन्हें लगता है कि लॉकडाउन 14 को समाप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी संभावना है तो वे बुकिंग शुरू कर सकती है। यदि लॉकडाउन स्थितियां बदलती हैं तो उन्हें उसके हिसाब से रणनीति बदलनी होगी।

कैंसिलेशन फीस लौटाने में आनाकानी या दिक्कत के प्रश्न पर उनका कहना था कि अचानक लॉकडाउन के कारण डोमेस्टिक एयरलाइंस तथा ट्रैवल एजेंट खुद को अजीब हालात में फंसा पा रहे हैं। उन्हें 25 मार्च से 14 अप्रैल के लिए कराई गई बुकिंग को कैंसिल कराने व रिफंड चाहने वालों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने कैंसिलेशन फीस माफ कर किराए की संपूर्ण राशि को क्रेडिट के तौर पर लॉकडाउन के बाद अगली उड़ानों के लिए सुरक्षित रखने का फैसला लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने विदेशों में फंसे अपने 1200 से अधिक यात्रियों को उड़ानों के जरिये स्वदेश पहुंचाया है। एयर इंडिया ने आज गुरुवार से दिल्ली से शंघाई के लिए कारगो उड़ाने शुरू कर दीं। दूसरी उड़ान आठ अप्रैल को होगी। इसी प्रकार छह, सात और नौ अप्रैल को दिल्ली से हांगकांग के लिए कारगो उड़ान की जाएंगी। ये बिना मुनाफे के आधार पर की जा रही है। हालांकि प्राइवेट एयरलाइंस कमर्शियल आधार पर पूरे किराए पर कारगो उड़ानें भर रही हैं।

चीन से चिकित्सा सामग्री लाने की एयर इंडिया को इजाजत

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना से निपटने की खातिर लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन के बीच एयर इंडिया को शंघाई व हांगकांग के लिए मालवाहक उड़ानों के संचालन के लिए भारतीय और चीनी अधिकारियों से मंजूरी मिल गई है। एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल ने बताया कि हमने चीनी अफसरों को दिल्ली से दो गंतव्यों- शंघाई और हांगकांग के लिए मालवाहक उड़ानों के संचालन का आवेदन दिया था। चीनी पक्ष की ओर से कुछ नियामक चुनौतियां रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाली फ्लाइट में चिकित्सा सामग्री होगी।

बंसल ने कहा, मुझे यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि हमें दो तारीखों- चार और पांच अप्रैल को दिल्ली से शंघाई के लिए व्यावसायिक उड़ानों के संचालन की मंजूरी मिल गई है। हमने छह, सात, आठ और नौ अप्रैल के लिए भी आवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि एक दिन के भीतर हमें इन तारीखों के लिए भी मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को हांगकांग के लिए कार्गो उड़ान संचालन की भी मंजूरी मिल गई है। हांगकांग के लिए स्वीकृति तेजी से मिली।

महिलाओं के बैंक खाते में जमा होने लगा पैसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आज से की जा सकेगी निकासी, अपनी बारी से ही जाएं बैंक, राज्य व जिला प्रशासन को भीड़भाड़ रोकने के निर्देश

लॉकडाउन से परेशानी उठा रही जनधन खाता धारक महिलाओं के बैंक खाते में सरकार की ओर से तीन अप्रैल से पैसे जमा कराए जाने लगेंगे, लेकिन स्वच्छता और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से पुख्ता बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि बैंक शाखाओं पर बेवजह भीड़ लगाने वालों पर सख्ती की जा सके। महिलाओं के जनधन खाते में केंद्र सरकार की ओर से अगले तीन महीने तक पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पांच सौ रुपये की धनराशि जमा कराई जाएगी।

खातों में पैसा जमा कराने के साथ सरकार ने लोगों को बैंक से धन निकालने के लिए तारीख भी तय कर दी है। लोगों को उसी हिसाब से बैंकों में पहुंचने को कहा है। इससे भीड़ से बचा जा सकेगा। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए इस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर बैंकों से पैसा निकालते समय कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन को इसके लिए पहले से ही ताकीद करने को कहा गया है।

जरूरतमंद महिलाएं अपने खाते से तीन अप्रैल से ही पैसा निकाल सकेंगी, लेकिन तीन अप्रैल को सिर्फ वही खाता धारक पैसा निकाल सकेंगे, जिसके बैंक खाते का अंतिम अंक 0 अथवा एक होगा। इसी तरह चार अप्रैल को वही लोग बैंक पहुंचे जिनके खाते का आखिरी नंबर 2 या तीन हो। सात अप्रैल को चार या पांच के अंक वाले खाताधारक पहुंचे। आठ अप्रैल को छह अथवा सात अंक वाले पहुंच सकते हैं। जबकि नौ अप्रैल को वो खाताधारक पहुंचें जिनके बैंक खाते का आखिरी नंबर आठ या नौ हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन के दौरान भीड़भाड़ न होना सुनिश्चित करने को कहा है।

तैयारी

दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगारों की मदद पर खर्च होगा बड़ा हिस्सा, राज्यों की स्वास्थ्य सेवा पर 1.6 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च का अनुमान

लॉकडाउन से उबारने के लिए राज्य भी देंगे 30,000 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर आर्थिक मदद दे रही हैं। इस दिशा में अभी तक देश के 10 राज्यों ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज का एलान किया है। सबसे अधिक केरल ने 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इन राज्यों में मुख्य रूप से लॉकडाउन से प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों के साथ बेरोजगारों की मदद की योजना बनाई गई है।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना ने कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2417 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 353 करोड़, पंजाब ने 116 करोड़, हरियाणा ने 1200 करोड़, हिमाचल प्रदेश ने 500 करोड़, तमिलनाडु ने 3280 करोड़, उड़ीसा ने 2200 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 200 करोड़ तो बिहार ने 100 करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया है। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि कोरोना महामारी एवं इससे बचने के लिए जरूरी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत है। इससे दिहाड़ी मजदूरों की जीविका पर संकट खड़ा होता दिख रहा है। ठीके पर और अस्थायी तौर पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के श्रमिकों व गरीबों की मदद के लिए कहा गया है। कई राज्य ठीके व अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी नौकरी जाने पर बेरोजगारी भत्ता देने की योजना भी बना रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी : कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य सेवा पर भी अतिरिक्त खर्च करना होगा। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए राज्य अगर अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की एक फीसद अतिरिक्त राशि स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं तो यह अतिरिक्त खर्च 1.6 लाख करोड़ रुपए का होगा।

महाराष्ट्र को बड़े पैमाने पर टेस्ट करने की मिली मंजूरी

मुंबई, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को खून की जांच के जरिये बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि त्वरित जांच के लिए राज्य सरकार स्वैब की जगह खून के नमूनों की जांच करेगी जिसके जरिये पांच मिनट में ही यह पता चल सकता है कि व्यक्ति में कोविड-19 के लिए एंटी-बॉडीज विकसित हुए हैं अथवा नहीं। केंद्र ने पहले महाराष्ट्र को बड़े पैमाने पर टेस्ट करने की अनुमति नहीं दी थी। वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राजेश टोपे और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शामिल हुए। टोपे ने आगे बताया, 'महाराष्ट्र में राज्य संचालित विभिन्न आश्रय स्थलों में करीब 3.25 लाख प्रवासी कामगार रह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है कि न सिर्फ उनके खाने-पीने का ध्यान रखें बल्कि उन्हें टेलीविजन भी उपलब्ध कराएं।

एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी राज्य ने स्वास्थ्य खर्च को अपने जीएसडीपी का 2 फीसद से अधिक नहीं रखा है। लेकिन कोविड-19 के फैलने के बाद स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी राज्यों की मजबूरी है अभी देश भर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 7,13,986 बेड की उपलब्धता है। भारत की मौजूदा आबादी को देखते हुए प्रति 1000 व्यक्ति पर 0.55 बेड की उपलब्धता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी